राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 807/2025

मांगी लाल दूधवाल पुत्र श्री हिता राम, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट सुदरासन जिला नागौर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, मार्फ़त प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर राजस्थान।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, राजस्थान सरकार, ब्लॉक-IV, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान।
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, मार्फ़त सचिव, अजमेर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : डॉ. निखिल डूंगावत

प्रतिवादी की ओर से:

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

13/02/2025

1. यहाँ याचिकाकर्ता ने, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए एक आकांक्षी होने के नाते, चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा की और असफल होने के बाद, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा दिए गए उत्तरों के मूल्यांकन के मानदंड को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष है।

2. उसकी शिकायत मुख्य रूप से दिनांक 11.09.2023 के शुद्धिपत्र (अनुलग्नक 6) की शर्तों के विरुद्ध निर्देशित है, जो इस प्रकार हैं:-

> *"1.* प्रत्येक प्रश्न में *1, 2, 3, 4, 5* के रूप में चिह्नित पाँच विकल्प हैं। आपको नीले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करके उत्तर पुस्तिका पर सही उत्तर को इंगित करने वाले केवल एक वृत्त *(*बुलबुला*)* को काला करना होगा।
>
> *2.* प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प भरना अनिवार्य है।

3. यदि आप किसी प्रश्न का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आपको वृत्त *'5'* को काला करना होगा। यदि पाँच में से कोई भी वृत्त काला नहीं किया जाता है, तो प्रश्न के अंकों का एक तिहाई *(1/3)* भाग काट लिया जाएगा।

4. प्रश्न पत्र हल करने के बाद, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच वृत्तों *(*बुलबुलों*)* में से एक को काला किया है। इसके लिए निर्धारित समय से परे *10* मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है।

5. एक उम्मीदवार जिसने *10%* से अधिक प्रश्नों में पाँच वृत्तों में से किसी को भी काला नहीं किया है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।"

3. तर्कों के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, न्यायालय के एक प्रश्न पर, कि याचिकाकर्ता ने उक्त शुद्धिपत्र को देरी से क्यों चुनौती दी है, वह जवाब देंगे कि याचिकाकर्ता को उक्त शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी नहीं थी। हालाँकि, यह अत्यधिक असंभव लगता है कि याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी नहीं होगी क्योंकि उक्त शुद्धिपत्र चयन अभिकरण - राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर विधिवत अपलोड किया गया था।

4. न्यायालय के एक और प्रश्न पर, कि उसे आज की तारीख में शुद्धिपत्र तक पहुँच कैसे मिली, वह जवाब देंगे कि उसने कुछ अन्य उम्मीदवारों से इसकी प्रति प्राप्त की है। अन्य उम्मीदवारों ने कैसे प्राप्त किया, इसका कोई जवाब नहीं है।

5. जो भी हो, यह प्रकट होता है कि शुद्धिपत्र में निर्धारित शर्तों को परीक्षा देते समय सभी उम्मीदवारों को विधिवत सूचित भी किया गया था, जैसा कि अनुलग्नक 3, जो ओ.एम.आर.-शीट है, से स्पष्ट है, जिसमें उसी के नीचे, उक्त शर्तों को स्पष्ट रूप से दोहराया गया है। यह प्रत्येक उम्मीदवार से अपेक्षित है कि परीक्षा देने से पहले, उसे लागू शर्तों को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही उत्तरों का प्रयास करना शुरू करना चाहिए। इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है कि याचिकाकर्ता ने उत्तर भरने से पहले निर्देशों को भी नहीं पढ़ा और यदि उसने ऐसा पढ़ा होता, तो जो गलतियाँ शुद्धिपत्र को न जानने के कारण सामने आई हैं, वे नहीं की जा सकती थीं।

6. जो भी हो, यदि याचिकाकर्ता ने शर्तों को नहीं पढ़ा, तो उसने अपने जोखिम पर ऐसा किया। इसलिए, यह तर्क देना कि उसे शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी नहीं थी, महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वही सामग्री ओ.एम.आर.-शीट में और पूरी संभावना है कि प्रश्न पत्र पर भी दोहराई गई है।

7. मैं याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से भी सहमत नहीं हूँ कि चूंकि शुद्धिपत्र विज्ञापन के बाद प्रकाशित हुआ था, इसलिए पूर्वव्यापी प्रकृति का होने के कारण, इसे लागू नहीं किया जा सकता था। शुद्धिपत्र विज्ञापन का निरंतरता मात्र है जो

परीक्षा से पहले जारी किया गया था और इसलिए, इसे मूल विज्ञापन की निरंतरता में पढ़ा जाना चाहिए और इस प्रकार, कोई पूर्वव्यापिता नहीं है। इसके अलावा, शुद्धिपत्र केवल उम्मीदवारों को सावधान करता है और दिशानिर्देश देता है कि उन्हें प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद उत्तरों का प्रयास कैसे करना था। शुद्धिपत्र के अभाव में भी, चयन अभिकरण प्रश्न पत्रों और/या ओ.एम.आर.-शीट में वही निर्देश देकर आवश्यक कार्रवाई कर सकती थी और उस हद तक, शुद्धिपत्र की भी आवश्यकता नहीं थी।

8. जहाँ तक समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के साथ याचिकाकर्ता की अयोग्यता का संबंध है, मुझे हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं मिलता है क्योंकि यह उनकी अपनी गलती के कारण हुआ है कि उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया।

9. अंत में, मैं यह जोड़ने की जल्दी कर सकता हूँ कि स्थापित कानून है कि उम्मीदवार, जो चयन प्रक्रिया में असफल रहा है, वह देरी से इस आधार पर इसे चुनौती देने के लिए मुड़ नहीं सकता है कि वह या तो मानदंडों से अनभिज्ञ था या अन्यथा सभी उम्मीदवारों पर लागू चयन अभिकरण द्वारा अपनाए गए मानदंड मनमाना थे और/या विज्ञापन के अनुरूप नहीं थे और/या अन्यथा भेदभावपूर्ण थे। ऐसे तर्क को स्वीकार करना उन लोगों के लिए शत्रुतापूर्ण होने के खतरे से भरा होगा जिन्होंने निर्देशों का सच्ची भावना से पालन किया है, उन लोगों के विपरीत जिन्होंने अपने जोखिम पर निर्देशों का पालन नहीं किया।

10. परिणामस्वरूप, मुझे हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं मिलता है।

11. खारिज किया जाता है।

12. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हो, भी निपटारा किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा), न्यायमूर्ति

44-एस.पी./एस.के.एम./-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़